

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
09.02.2022 के
अतारांकित प्रश्न सं. 1217 का उत्तर

नई रेल लाइन का निर्माण

1217. श्री अक्षयवर लाल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का विचार खलीलाबाद, उतरौला, डुमरियागंज, भिंगा, श्रावस्ती और बलरामपुर के लिए नई रेलवे लाइन के निर्माण का है;
- (ख) क्या सरकार को बहराइच होते हुए जरवल तक उक्त मार्ग लाइन बिछाने का कोई पत्र प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त रेल लाइन का अधिकतम उपयोग करने के लिए इसे बिछाए जाने की संभावना है;
- (ग) यदि हां, तो उक्त रेलवे लाइन का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है; और
- (घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क): बहराइच-खलीलाबाद बरास्ता भिंगा, श्रावस्ती, बलरामपुर (तुलसीपुर), उतरौला, डोमरियागंज, बंसी एवं मेधवाल (240 किमी) नई लाइन परियोजना को बजट 2016-17 में शामिल किया गया था और 4939.78 करोड़ रु. की लागत पर 31.10.2018 को स्वीकृत किया गया था।

इस परियोजना के लिए कुल 1060 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। 779.246 हैक्टेयर के लिए भूमि योजनाओं को सत्यापन के लिए जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर को प्रस्तुत किया गया है।

(ख): जी नहीं। परियोजना को स्वीकृत संरेखण के अनुसार नियोजित किया जाता है।

(ग) और (घ): किसी भी परियोजना का समय से पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन संबंधी स्वीकृति, बाधक उपयोगिताओं का अंतरण, विभिन्न प्राधिकारियों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना साइट के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु स्थिति को ध्यान में रखते हुए परियोजना विशेष साइट के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है और ये सभी कारक परियोजना के समापन को प्रभावित करते हैं। अतः, परियोजना के पूरा होने के लिए निश्चित समय-सीमा नहीं दी जा सकती है।

2014-19 के दौरान, उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाले अवसंरचनात्मक और संरक्षा कार्यों पर औसत वार्षिक बजट आबंटन, 2009-14 के दौरान, 1,109 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 5278 करोड़ रुपए प्रति वर्ष किया गया है, जो 2009-14 के औसत वार्षिक बजट परिव्यय से 376% अधिक है। वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए इन परियोजनाओं हेतु बजट परिव्यय क्रमशः 8403 करोड़ रुपये तथा 8576 करोड़ रुपये दिया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में अब तक का सर्वाधिक बजट परिव्यय 12,696 करोड़ रुपये मुहैया कराया गया है, जो 2009-14 के औसत वार्षिक बजट परिव्यय से 1045% अधिक है।

2014-21 के दौरान, उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली 2032 किमी खण्डों (204 किमी नई लाइनें, 631 किमी आमान परिवर्तन और 1197 किमी दोहरीकरण) को 290.29 किमी./वर्ष की औसत दर पर यातायात के लिए खोल दिया गया है, जो 2009-14 के दौरान (199.2 किमी./प्रतिवर्ष) यातायात के लिए चालू किए गए किमी. से 42% अधिक है।
